सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें

फोनः 0141-2202717

मो: 9214203182

वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-259 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, शनिवार 24 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

राजस्थान में नौतपा को लेकर IMD की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

जयपुर। जयपुर। नौतपा की शुरुआत 25 मई से होगी। इससे पहले मौसम वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की मानें तो राजस्थान में इस बार नौतपा में बारिश होने की संभावना है। ऐसे में नौतपा के दिनों में प्रदेशवासियों को लू के थपेड़ों से काफी हद तक राहत मिलेगी।

बता दें कि नौतपा की अवधि 25 मई से लेकर 2 जून तक रहेगी। इन 9 दिन की अवधि में सूरज सर्वाधिक आग उगलता है। झुलसाने वाली धूप और लू चरम पर होती है। लेकिन, इस बार नौतपा में मौसम में बदलाव होने के आसार हैं।

नौतपा में तीन दिन यहां बारिश का अलर्ट

25 मई-अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और जालोर में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सीकर में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

पाली और जालोर में येलो अलर्ट जारी किया है।

26 मई= मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर और जालोर में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

27 मई= मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, श्रीगंगानगर, पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर, हनुमानगढ़ व चूरू में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में 47 डिग्री का प्रहार, दक्षिण में बादल कर रहे वार, मानसून की आहट दक्षिण भारत में

जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक विशेष मौसम चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि दक्षिण कोंकण तट से दूर पूर्व-मध्य अरब सागर पर आज सुबह 8.30 बजे एक सुस्पष्ट निम्न दाब का क्षेत्र बना है, जो अगले 24 घंटों में और अधिक तीव्र होकर उत्तर की ओर बढ़ सकता है। इससे देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, वहीं राजस्थान सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर बरकरार रहेगा।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण कोंकण तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर पर आज 23 मई एक सुस्पष्ट निम्न दाब का क्षेत्र स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर की ओर बढ़ने और एक अवदाब में और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

पश्चिमी तट (गुजरात, कोंकण और गोवा, कर्नाटक और केरल) पर अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, कोंकण और गोवा में 23-25 मई के दौरान, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 24-27 मई के दौरान, मध्य महाराष्ट्र में 25 मई को, तमिलनाडु के घाट क्षेत्र में 25 मई और 26 मई को अत्यंत भारी वर्षा की केरल में अगले 2 दिनों के दौरान मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान में 23-27 मई के दौरान, जम्मू और कश्मीर में 23-26 मई के दौरान और पूर्वी राजस्थान में 23-25 ??मई के दौरान उष्ण लहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है।

क्या है नौतपा

नौतपा वह समय होता है जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं। इससे गर्मी का असर बहुत बढ़ जाता है। जब सूर्य मृगाशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब नौतपा समाप्त हो जाता है। यह 9 दिनों की अवधि होती है।

बीजेपी विधायक की सदस्यता खत्म

अशोक गहलोत ने पूछा- फैसला लेने में 23 दिन क्यों लगाए? स्पीकर पर लगाए आरोप

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा मोड़ तब आया जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अंता से विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। मीणा को 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में तीन साल की सजा मिली है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।

गहलोत ने भी उठाए देरी पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले में देरी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कंवरलाल मीणा की सदस्यता तो उसी दिन समाप्त कर देनी चाहिए थी, जिस दिन उन्हें सजा सुनाई गई। आरपी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दोनों ही स्पष्ट हैं कि सजा मिलते ही सदस्यता खत्म मानी जानी चाहिए। गहलोत ने सवाल किया कि जब नियम साफ हैं, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लेने में 23 दिन क्यों लगा दिए? उन्होंने आरोप लगाया कि यह देरी भाजपा सरकार के दबाव में की गई।

'प्रदेश सरकार निष्क्रिय'- गहलोत

गहलोत ने केवल विधायक सदस्यता ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार की प्रशासनिक निष्क्रियता पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गर्मी में मज़दूर की मौत, पानी की किल्लत, बेरोजगारी, इन सब समस्याओं पर सरकार का कोई

प्रयास नज़र नहीं आ रहा। जनता को लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। गहलोत ने बीकानेर, चुरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे जिलों में भीषण जल संकट की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया।

डोटासरा ने भी साधा निशाना

वहीं, गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर कहा कि कांग्रेस के दबाव और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के चलते ही भाजपा को कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करनी पड़ी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है और कांग्रेस बार-बार ऋस् और भाजपा को यह याद दिलाती रहेगी। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने जानबूझकर निर्णय में देरी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कई बार ज्ञापन देकर चेताया, फिर भी दोषी विधायक को बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते। अंततः सत्य की जीत हुई। डोटासरा ने यह भी कहा कि कांग्रेस संविधान और कानून की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की आदत-राज्यवर्धन सिंह राठौर

जयपुर। राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने %ऑपरेशन सिंदूर% को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर शुक्रवार को तीखा पलटवार किया।

राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि कांग्रेस बार-बार भारतीय सेना की वीरता और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करती है। चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या अब ऑपरेशन सिंदूर, कांग्रेस की आदत बन गई है कि वह हर बार सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करती है।

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकवादियों के अड्डों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। यह ऑपरेशन पुलवामा हमले का बदला लेने में एक बड़ी सफलता है। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई से देश का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अगर भविष्य में कोई कायराना हमला हुआ, तो पाकिस्तान को, उसकी सेना को और उसकी अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

राठौर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता इस ऑपरेशन को पूरे सम्मान के साथ देख रही है और सेना के साथ खड़ी है। राहुल गांधी देश की जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों और पाकिस्तान के लिए सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता सत्ता के लालच में देश और सेना के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं।

पाकिस्तान की ओर से परमाणु हथियारों की धमकी को %गीदड़ भभकी% करार देते हुए राठौर ने कहा कि अब भारत न तो डरने वाला है और न ही ब्लैकमेल होने वाला है। हमारी सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। एक संवेदनशील पड़ोसी देश को मानवीयता दिखानी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।

वन विभाग को भूमि आवंटन की दी स्वीकृति

जयपुर,। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में ईआरसीपी परियोजना (रामजल सेतु लिंक परियोजना) के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत बारां एवं अलवर जिलों में 1102.72 हैक्टेयर भूमि वन विभाग को आंवटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के अंतर्गत निर्माणाधीन रामगढ़ एवं महलपुर बैराज तथा नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के अन्तर्गत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को भूमि आंवटन के चार प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। इस निर्णय के अनुसार बारां जिले की किशनगंज तहसील में 427.59 हैक्टेयर, छबड़ा तहसील में 284.09 हैक्टेयर, छीपाबड़ौद तहसील में 362.95 हैक्टेयर एवं अलवर जिले में आरक्षित भूमि कोष से 28.08 हैक्टेयर गैर-वन भूमि वन विभाग को निःशुल्क आंवटित की जा रही है।

राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का तोहफा

जयपुर। सुशासन को समर्पित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पांचवें एवं छठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य

कर्मचारियों एवं पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी, 2025 से क्रमशः 11 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की वृद्धि के निर्णय पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 455 प्रतिशत से बढ़कर अब 466 प्रतिशत एवं छठे वेतनमान में 246 प्रतिशत से बढ़कर अब 252 प्रतिशत हो गया है।'आपणो अग्रणी राजस्थान' के विजन के अनुरूप प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के सर्वांगीण उत्थान हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है।

कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता-कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी ऐप (Betting Apps Ban) पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने इसकी सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ सामाजिक विकृतियां हैं, जिनमें लोग स्वेच्छा से लिप्त होते हैं।

'लोग स्वेच्छा से हो रहे शामिल'

कोर्ट ने याचिका की एक प्रति अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को मुहैया कराने का निर्देश दिया, ताकि मामले में उनकी सहायता ली जा सके। कोर्ट ने कहा कि आप इस गलतफहमी में हैं कि इन

गतिविधियों को कानून के ज़रिए रोका जा सकता है। लोग स्वेच्छा से इसमें शामिल हो रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा जिस तरह हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता।

याचिकाकर्ता ने किया ये दावा

याचिकाकर्ता के.ए. पॉल ने दावा किया कि अभिनेता, इन्फ्लुएंसर, साथ ही एक प्रमुख क्रिकेटर, इन ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं, जिससे युवा सट्टेबाजी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने इसे जुआ घोषित कर प्रतिबंधित करने की मांग की, यह कहते हुए कि यह समाज के लिए हानिकारक है।

तेलगांना की मौतों का किया जिक्र

याचिकाकर्ता ने कहा कि यहां पर मैं उन लाखों माता-पिता की ओर से हूं, जिनके बच्चे मर गए। तेलंगाना में 1023 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि लोगों पर सट्टेबाजी ऐप का बहुत बुरा असर पड़ रहा है।

IPL के दौरान कर रहे प्रचार

याचिकाकर्ता ने कहा कि सट्टेबाजी से जुड़े ऐप के मामले में कोई सावधानी नहीं बरती गई। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटरों ने भी आईपीएल के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले ऐप का प्रचार किया।

राजस्थान में भाजपा विधायक की सदस्यता खत्म, SDM पर तानी थी पिस्तौल

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कानूनी सलाह के आधार पर यह फैसला लिया।

बता दें कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा दी गई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी 1 मई 2025 से समाप्त मानी जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

कंवरलाल मीणा पर वर्ष 2003 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी (स्डरू) पर पिस्तौल तानने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप थे। इस मामले में हाल ही में अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई।

कंवरलाल मीणा ने सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए उन्हें दो सप्ताह में सरेंडर करने के निर्देश दिए। इसके बाद 21 मई 2025 को उन्होंने अकलेरा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, और फिलहाल जेल में बंद हैं। बताते चलें कि कंवरलाल मीणा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया को 5,861 वोटों से हराकर अंता सीट से विधायक बने थे। लेकिन महज डेढ़ साल में ही उनका विधायक पद चला गया।

विधानसभा अध्यक्ष का फैसला

विधानसभा सचिवालय ने मीणा को नोटिस भेजकर 7 मई तक जवाब मांगा था, जिसमें यह पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई अंतरिम राहत मिली या नहीं। लेकिन सजा पर रोक न लगने की पुष्टि के बाद स्पीकर के पास विधायकी रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

महाधिवक्ता (AG) और वरिष्ठ विधिवेताओं की राय के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने आज यह फैसला किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का हवाला भी शामिल था, जिसके अनुसार दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है।

8 साल में दूसरी बार सदस्यता खत्म

यह घटना राजस्थान विधानसभा में आठ साल में दूसरी बार किसी विधायक की सदस्यता समाप्त होने का मामला है। इससे पहले 2017 में बसपा विधायक बीएल कुशवाह को हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता खत्म की गई थी। उस समय धौलपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनकी पत्नी शोभारानी कुशवाह भाजपा के टिकट पर विजयी हुई थीं।

इस बार भी नहीं टूटी परिपाटी, विधानसभा में फिर आया '199' का फेर

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर '199' विधायकों का आंकड़ा चर्चा में आ गया है। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब विधानसभा में केवल 199 विधायक रह गए हैं। कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा मिली है, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की।

हालांकि, उपचुनाव के बाद इस बार विधानसभा ने कुछ समय के लिए 200 विधायकों की पूर्णता देखी थी, लेकिन अब एक बार फिर से सदन 199 के रहस्यमयी आंकड़े पर आ गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक एक साथ नहीं रह पाए हों।

भजनलाल सरकार में भी 199 का फेर

दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव भी 199 सीटों पर ही कराए गए थे, क्योंकि श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते चुनाव स्थगित कर दिया गया था। बाद में उपचुनाव में रूपेंद्र सिंह विजयी होकर सदन पहुंचे। इससे पहले साल 2018 और 2013 में भी 199 सीटों पर चुनाव कराए गए थे।

फिर सरकार बनते ही बागीदौरा से कांग्रेसी विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने आखिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। मालवीय के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में फिर से 199 के आंकड़े का फेर शुरू हो गया था।

वहीं, अलवर की रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान का निधन होने पर यह सीट खाली हो गई थी। उदयपुर की सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद खाली हो गई थी। इसके अलावा 5 विधायकों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, इस वजह से राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इन उपचुनावों के बाद राजस्थान में फिर से 200 विधायक हो गए थे, लेकिन अब अंता विधायक कंवरलाल मीणा के निष्कासन के साथ फिर से यह संख्या 199 पर पहुंच गई है।

विधानसभा भवन से जुड़ी रहस्यमयी धारणाएं

गौरतलब है कि ज्योति नगर स्थित राजस्थान विधानसभा भवन वर्ष 2001 में नए परिसर में स्थानांतरित हुआ, लंबे समय से वास्तु दोषों और अनहोनी घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा है। वास्तु शास्त्र के जानकारों की मानें तो यह भवन पूर्व में श्मशान भूमि पर बनाया गया था। साथ ही, भवन का दक्षिणी भाग नीचा है और पश्चिम द्वार का उपयोग वास्तु नियमों के विपरीत बताया जाता है।

यही नहीं, निर्माण के दौरान करीब आधा दर्जन मजदूरों की मौत भी इस इमारत को लेकर रहस्य और डर की आभा पैदा करती है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जैसे नेताओं ने तो इस भवन को **गंगाजल से धोने तक की मांग की थी।**

वहीं, पिछले कुछ समय में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाने की स्थिति पर ज्योतिष और वास्तुविदों से राय ली थ और विधानसभा के गेट नंबर 5 और 6 को बंद कर पूर्वी द्वार से प्रवेश अनिवार्य किया गया।

क्या वाकई है '199 का शाप'?

अब यह केवल संयोग है या कुछ और, लेकिन यह सच है कि 24 साल के इतिहास में कभी भी पूरे कार्यकाल तक विधानसभा में 200 विधायक एक साथ नहीं टिके हैं। कभी किसी विधायक का निधन, कभी कोई अपराध में दोषी, तो कभी सांसद चुने जाने पर इस्तीफा, कोई न कोई सीट खाली हो ही जाती है। इससे पहले पिछली गहलोत सरकार के दौरान भी बीएल कुशवाह की सदस्यता हत्या के केस में खत्म हुई थी। जिसके चलते विधानसभा में 199 सदस्य रह गए थे।

राजस्थान विधानसभा भवन का यह इतिहास अब मिथक और तथ्य के बीच की बहस बन गया है। चाहे वह वास्तु दोष हो, कोई धार्मिक आस्था, या फिर केवल राजनीतिक संयोग, लेकिन '200 का आंकड़ा राजस्थान विधानसभा में स्थायी क्यों नहीं रह पाता?' यह सवाल अब जनता से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंजने लगा है।

भारत की जल कूटनीति से पाकिस्तान लाचार

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर संघर्षविराम का जो निर्णय लिया है, उसके बहुतेरे अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। यह स्थिति चूंकि पाकिस्तान द्वारा लाई गयी थी, इसलिए इस मसले पर पाकिस्तान के पीछे हटने पर भारत को सीजफायर मानना पड़ा। अब भारत, स्पष्ट कर चुका है कि आपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता।

सिंधु संधि स्थगन

ज्ञानेन्द्र रावत

भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को नियंत्रित करने के साथ ही नदियों से संबंधित डाटा भी साझा करना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के बावजूद भारत ने सिंधु जल संधि का सम्मान किया लेकिन अब भारत इस पर कोई समझौता नहीं करेगा।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय अब पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा है। हालांकि, भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के निर्णय के बाद सैन्य अभियानों पर अस्थायी विराम लगा है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पश्चात भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई निर्णय और प्रतिबंध यथावत लागू हैं। इन निर्णयों में सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तान को निर्यात पर रोक, वीज़ा प्रतिबंध तथा राजनयिक संबंधों में कटौती जैसे कदम शामिल हैं।

दरअसल, सीज़फायर के बावजूद पाकिस्तान की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती सिंधु जल समझौते के स्थगन को लेकर है, क्योंकि अब भारत इन नदियों के जल प्रवाह को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है — चाहे तो जल रोके या छोड़े। यह एक निर्विवाद सत्य है कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत सिंधु बेसिन की तीन प्रमुख नदियां— झेलम, चिनाब और सिंधु— का लगभग 80 प्रतिशत जल पाकिस्तान को मिलता था, जबकि भारत को केवल 19.5 प्रतिशत जल प्राप्त होता था।

उल्लेखनीय है कि भारत अपने हिस्से के जल का भी लगभग 90 प्रतिशत ही उपयोग करता था। लेकिन सिंधु जल समझौते के स्थगन के बाद भारत ने अपने हिस्से के जल को पूरी तरह रोकना शुरू कर दिया। इसके साथ ही, जब भारत के बांधों में जल स्तर बढ़ता है, तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के अतिरिक्त जल छोड़ देता है। पाकिस्तान की कृषि, पेयजल आपूर्ति और उसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सिंधु बेसिन से बहने वाली नदियों पर निर्भर है। सिंधु बेसिन की छह प्रमुख नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं— जिनमें तीन पूर्वी प्रवाह वाली नदियां हैं सतलुज, ब्यास और रावी और तीन पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु। इनमें से पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों— झेलम, चिनाब और सिंधु— का अधिकांश जल पहले पाकिस्तान को मिलता था। लेकिन सिंधु जल समझौते के स्थगन के बाद भारत अब इन नदियों के जल को रोक रहा है। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था ही नहीं, अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर संघर्षविराम का जो निर्णय लिया है, उसके बहुतेरे अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। यह स्थिति चूंकि पाकिस्तान द्वारा लाई गयी थी, इसलिए इस मसले पर पाकिस्तान के पीछे हटने पर भारत को सीजफायर मानना पड़ा। अब भारत, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से मिली अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठायेगा जो स्वाभाविक है। वहीं भारत, स्पष्ट कर चुका है कि आपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। फिलहाल भारत सरकार सिंधु जल समझौता बहाल करने को तैयार नहीं है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे को विश्व बैंक ले जाने का प्रयास किया था लेकिन वहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। विश्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मसले में एक मध्यस्थ की भूमिका में था। इसके आगे विश्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। पाकिस्तान अब इस मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी में लगा है। भारत स्पष्ट कर चुका है कि उसने समझौते के प्रारूप के तहत ही समझौते के स्थगन का कदम उठाया है। पाकिस्तान का इस संदर्भ में कहना है कि अगर सिंधु जल समझौते को भारत द्वारा खत्म किया जाता है और उसकी तरफ आने वाले पानी को रोका जाता है तो वह इसे युद्ध मानेगा। अपनी ओर से इसका हरसंभव विरोध करेगा।

एक ओर पाकिस्तान इस मुद्दे का पुरजोर विरोध करने की बात कर रहा है, वहीं वह भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय से समझौते के स्थगन के फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार भी लगा रहा है। यही नहीं, भारत से सीधे बातचीत के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने इस बाबत संकेत भी दिये हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी दिल्ली की दीर्घकालीन चिंताओं पर चर्चा करने के इच्छुक हैं। पाकिस्तान के अनुरोध पत्र को भारतीय जलशक्ति मंत्रालय ने इस समझौते के लिए अधिकृत विदेश मंत्रालय को भेजा है जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार का सवाल ही नहीं उठता। भारत अब इन तीन नदियों के पानी को अपने लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इस पर काम भी जारी है। साथ ही मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से देश को काफी लाभ होगा। समझौता स्थगन के दौर में भारत सिंधु बेसिन के तहत आने वाली छह नदियों का पानी अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। भारत में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को अपनी खेती और पेयजल के अलावा दूसरी जरूरतों को पूरा करने हेतु ज्यादा पानी मिलेगा।

रावी, ब्यास और सतलुज के इस पानी का लाभ समझौते के स्थगन के मौजूदा हालात में इन राज्यों को वर्तमान में मिल भी रहा है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में भी इस समय पानी की आवक बढ़ गयी है। उम्मीद है कि इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब के बीच बरसों से जारी जल विवाद भी थम जायेगा। फिर उत्तर भारत में ज्यादा पानी मिलने से भाखड़ा सहित विभिन्न बांधों में बिजली उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। सिंधु जल समझौता स्थगन पाकिस्तान में उसकी बहुत बड़ी आबादी के लिए पेयजल संकट का भयावह रूप धारण कर लेगा। पानी तो इतना बड़ा मुद्दा है जो पाकिस्तान को कुछ ही महीनों में भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर देगा।

भारत ने पाकिस्तान को जाने वाले पानी को नियंत्रित करने के साथ ही नदियों से संबंधित डाटा भी साझा करना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के बावजूद भारत ने सिंधु जल संधि का सम्मान किया लेकिन अब भारत इस पर कोई समझौता नहीं करेगा।

लेखक पर्यावरणविद हैं।

संपादकीय

निर्ममता और नादानी

कैथल जनपद के गांव धनौरी में दो किशोरों की निर्मम हत्या की हृदयविदारक घटना उद्वेलित करने वाली है। चौदह-पंद्रह साल के दो किशोरों की गला रेतकर हत्या कर देना और वह भी उनके हमउम्र साथियों द्वारा, हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली घटना है। जाहिर है दसवीं-ग्यारहवीं के छात्रों की क्रूर हत्या हमारे समाज में बढ़ती आक्रामकता और संवेदनहीनता को भी दर्शाती है। बताते हैं हत्या में शामिल युवक गांव के ही थे और कुछ दिन पहले किशोरों को धमकाने उनके घर आए थे। इस बाबत प्रकाशित खबरों के अनुसार मारे गए किशोरों पर हत्या आरोपियों ने आरोप लगाया था कि वे उनकी बहनों से छेड़खानी करते थे। निश्चय ही ऐसे छेड़खानी के कथित आरोप को नैतिक दृष्टि से अनुचित ही कहा जाएगा, लेकिन उसका बदला हत्या कदापि नहीं हो सकती। यह हृदयविदारक है कि एक मृतक किशोर अरमान पांच बहनों का अकेला भाई था। घटना से उपजी त्रासदी से अरमान के परिवार पर हुए वज्रपात को सहज महसूस किया जा सकता है। उनके लिये जीवनभर न भुलाया जा सकने वाला दुख पैदा हुआ है। बहरहाल, किसी परिवार की उम्मीदों का यूं कत्ल होना मर्मांतक ही है। लेकिन सवाल ये है कि चौदह-पंद्रह साल के किशोरों पर यूं किन्हीं लड़कियों को छेड़ने के आरोप क्यों लग रहे हैं? पढ़ने-लिखने की उम्र में ये सोच कहां से आ रही है? क्यों हमारी परिवार संस्था बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पा रही है ताकि वे किसी की बेटी व बहन को यूं परेशान न करें? उन्हें क्यों लगता है कि किसी लड़की को छेड़ा जाना चाहिए? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में नैतिक शिक्षा का वह पक्ष तिरोहित हो चला है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है? क्या शिक्षक छात्रों को सदाचारी व नैतिक मूल्यों का जीवन जीने की प्रेरणा देने में विफल हो रहे हैं? हत्या की घटना हत्यारों की मानसिकता पर भी सवाल उठाती है कि उन्होंने क्यों सोच लिया कि छेड़खानी का बदला क्रूर ढंग से गला काटना हो सकता है? दरअसल, दशकों तक बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों ने समाज में जिस अपसंस्कृति का प्रसार किया, आज हमारा समाज उसकी त्रासदी झेल रहा है। आम तौर पर फिल्मों में हीरो हिरोइन से छेड़खानी करता और उसे परेशान करता नजर आता था। बाद में फिल्म की पटकथा में नायिका उसी हीरो के आगे समर्पण करती नजर आती थी। फिर फिल्म की पटकथा इस छेड़खानी को प्रेम कथा और विवाह में तब्दील कर देती है। कालांतर समाज के किशोरवय और युवाओं में यह संदेश गया कि निजी जीवन में यही छेड़खानी उनकी प्रेम कहानी में तब्दील हो सकती है। फिर बची-खुची कसर हमारे टीवी धारावाहिकों की संवेदनहीन व क्रूर-कथाओं ने पूरी कर दी। बॉक्स आफिस की सफलता और टीआरपी के खेल ने मनोरंजक कार्यक्रमों में ऐसी नकारात्मकता भर दी कि समाज में इसे न्यू नॉर्मल मानने की सोच पैदा हुई। कहीं न कहीं पारिवारिक संस्था व शिक्षा व्यवस्था इस सोच को खारिज करने में चूकी है। इंटरनेट के विस्तार और सोशल मीडिया के प्रसार से स्वच्छंद यौन व्यवहार का ऐसा अराजक रूप सामने आया कि जिसने किशोरों व युवकों को पथभ्रष्ट करना शुरू कर दिया। आज संकट ये है कि हर किशोर के हाथ में आया मोबाइल उसे समय से पहले वयस्क बना रहा है। जिस पर न परिवार का नियंत्रण है और न ही शिक्षकों का। कोरोना संकट के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं की अपरिहार्यता ने विद्यार्थियों को मोबाइल उपयोग की स्वच्छंदा दी। आज उन्हें प्रभावित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व एप पश्चिमी अपसंस्कृति से संचालित हैं। इन पर अश्लीलता और यौन-विकृतियों वाले कार्यक्रमों का बोलबाला है। उन कार्यक्रमों की बाढ़ है जिनमें हमारे पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में स्वच्छंद यौन व्यवहार को हकीकत बताने का खेल चल रहा है।

विकास उड़ गया आंधी में

(लेखिका - निर्मल रानी)

दिल्ली-एनसीआर को गत दिनों तेज़ आंधी,बारिश व तूफ़ान का सामना करना पड़ा। इस तेज़ आंधी में नई दिल्ली स्टेशन के क़रीब नबी करीम क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई जिसमें दब जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गये। जबकि कई जगहों पर पेड़ उखड़ने का भी समाचार है। परन्तु शायद इस आंधी का सबसे अधिक प्रकोप न्यू अशोक नगर रैपिड मेट्रो स्टेशन को झेलना पड़ा। दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ रैपिड मेट्रो रेलवे ट्रांज़िट सिस्टम के बीच आने वाले इस स्टेशन के एक बड़े हिस्से की छत ही तेज़ हवा के चलते उड़ गई। और छत की कई टीन नीचे सड़क पर जा गिरी तो कई हवा में लटकने लगीं। ग़ौर तलब है कि अभी क़रीब चार माह पूर्व ही 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली-मेरठ रेपिड रेलवे ट्रांज़िट सिस्टम के 13 किलोमीटर लंबे जिस सेवशन का उद्घाटन किया था, न्यू अशोक नगर स्टेशन भी उसी सेवशन के बीच आने वाला एक प्रमुख स्टेशन है। और यह नवनिर्मित स्टेशन आंधी-तूफ़ान का एक झटका भी नहीं झेल पाया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से जोड़ने वाली इस परियोजना में 4,600 करोड़ रुपये की लागत आई है। न्यू अशोक नगर रैपिड मेट्रो स्टेशन पर हुये इस हादसे के बाद सुरक्षा के दृष्टिगत नमो भारत ट्रेन की सेवाओं के आवागमन को अगले आदेश तक स्थगित करना पड़ा था। इस हादसे के बाद एक बार फिर स्टेशन की छत के निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न उठने लगे हैं।

यहाँ एक बात यह भी क़ाबिले ग़ौर है न केवल प्रधानमंत्री नई ट्रेन को झंडी दिखा कर रवाना करते हैं बल्कि पुल,हाईवे एक्सप्रेसवे के छोटे से नवनिर्मित हिस्से जैसी परियोजनाओं का भी वे स्वयं उद्घाटन करते हैं बल्कि ऐसे अवसरों पर प्रायः कांग्रेस की सरकार को कोसने और अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूकते। मिसाल के तौर पर गत वर्ष द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने तंज़ करते हुये कहा था कि फ्कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वे अब तेज़ी से भरे जा रहे हैं। उसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि मैं न छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं और न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो चाहिए विराट चाहिए, विशाल चाहिए और तेज़ गति से चाहिए क्योंकि 2047 में मुझे देश को 'विकसित भारत' के रूप में देखना है। परन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे हर परियोजना का निर्माण टिकाऊ व मज़बूत भी चाहिये। याद कीजिये 16 जुलाई को प्रधानमंत्री ने ज़िला जालौन के कैथेरी में पूरे प्रचार-प्रसार के साथ जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया था वह एक्सप्रेस-वे उद्घाटन के केवल 5 दिन बाद ही जगह-जगह से धंस गया था और उसमें कई जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ गये थे। जिसके कारण कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे। चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा के कुदरेल में मिलने वाले इस बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण पर क़रीब 14 हज़ार करोड़ की लागत आई थी। इसके एक वर्ष बाद फिर इसी एक्सप्रेस वे पर पुनः चित्रकूट को जाने वाली लेन पर क़रीब एक दर्जन गड्ढे हो गए थे। इन गड्ढों में पानी भरने से एक्सप्रेस वे से निकलने वाले कई वाहनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा था। उस समय भी मीडिया में इस परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किये गए थे और काफ़ी घटिया निर्माण के चलते सरकार की काफ़ी फ़ज़ीहत हुई थी। ज़ाहिर है यह गड्ढे कांग्रेस के समय के नहीं थे।

इसी तरह देश के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा ज़िले के भांडारेज के पास पर भारी वाहन गुज़रने से सड़क धंस गई, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया था। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। यहाँ भांडारेज टोल के पास भारी वाहन गुज़रने मात्र से सड़क धंस गई थी जिससे सड़क के बीचों-बीच 15 फ़ुट गहरा गड्ढा हो गया था । इस एक्सप्रेस वे पर गड्ढे होने के बाद इसमें भी घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल तथा लापरवाही का आरोप लगा था। इस परियोजना के निर्माण पर भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की लागत आई थी। 12 फ़रवरी 2023 को इस का भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही उद्घाटन किया था और उद्घाटन करते हुये इसे भी देश की आधारभूत संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया था। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही महीनों में बारिश ने इस उत्कृष्ट निर्माण की वास्तविकता को उजागर कर दिया था। इस तरह के दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो या तो निर्माण के समय ही ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गये या उद्घाटन के कुछ समय बाद ही उनकी असलियत उजागर हो गई। अभी गत वर्ष बिहार में इसतरह एक के बाद एक कई बड़े पुल ढह गए। गत वर्ष अयोध्या नगरी में कई जगह सड़कें धंस गयीं। चंडीगढ़ से राजस्था को जाने वाला अंबाला से होकर गुज़रने वाला हाइवे अपने निर्माण के कुछ ही समय बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। इसपर बने कई पुल भारी वहां गुज़रने पर आज भी थरथर हिलते हैं। यह सारे गड्ढे विकसित राष्ट्र के मार्ग में पड़ने वाले गड्ढे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी न ही कांग्रेस की है न ही पंडित नेहरू की।

सवाल यह है कि इस तरह के घटिया निर्माण के पीछे का रहस्य आख़िर क्या है ? कौन हैं इन कंपनीज़ के मालिक जो जनता के टैक्स के पैसों की इसतरह खुलकर लूट करते हैं ? जनधन की लूट खसोट का यह सिलसिला आख़िर कभी ख़त्म भी होगा या नहीं ? इन लुटेरी निर्माण कंपनियों को किसकी शह मिली हुई है ? क्या वजह है कि जिन मुग़लों को विदेशी व आक्रांता बताकर दिन रात वोट बटोरने की राजनीति की जाती है उनके समय के बनाये हुये हज़ारों निर्माण आज भी पूरी मज़बूती के साथ अपना सिर बुलंद किये खड़े हैं। इसी तरह अंग्रेज़ों के शासनकाल के अनेक महत्वपूर्ण निर्माण आजतक क्षतिग्रस्त नहीं हुये। उदाहरणार्थ 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटित व ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किये गये पुराने संसद भवन का आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ जबकि सेन्ट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत बना नया संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था उसमें पहली बारिश के दौरान ही पानी टपकने लगा था। निश्चित रूप से यह इस भवन की गुणवत्ता या निर्माण में कमी के कारण ही था। इससे नये संसद भवन की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची थी। परन्तु आश्चर्य है कि भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस व विकास का हर वक़्त ढिंढोरा पीटने वाली सरकार का विकास कहीं गड्ढों में घुसा जा रहा है तो कहीं आंधी में उड़ा जा रहा है ?

(यह लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

(चिंतन-मनन)

प्रतिभा और ज्ञान

एक संत को जंगल में एक नवजात शिशु मिला। वह उसे अपने घर जे आए। उन्होंने उसका नाम जीवक रखा। उन्होंने जीवक को अच्छी शिक्षा-दीक्षा प्रदान की। जब वह बड़ा हुआ तो उसने संत से पूछा, गुरुजी, मेरे माता-पिता कौन हैं? संत को जीवक के मुंह से यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन उन्होंने उसे सच बताने का निश्चय किया और बोले, पुत्र, तुम मुझे घने जंगलों में मिले थे। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे माता-पिता कौन हैं और कहां हैं? जीवक अत्यंत उदास होकर बोला, गुरुजी, अब आत्महीनता का भार लेकर मैं कहां जाऊं? इस पर संत उसे सांत्वना देते हुए बोले, पुत्र, इस बात से दुखी होने के बजाय तुम तक्षशिला जाओ और वहां विद्याध्ययन करके अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण समाज को आलोकित करो। जीवक अध्ययन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर वहां के आचार्य को उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया।

आचार्य ने उसकी स्पष्टवादिता से प्रभावित होकर उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश दे दिया। जीवक वहां पर कठोर परिश्रम के साथ विद्या प्राप्त करने लगा। वहां उसने आयुर्वेदाचार्य की उपाधि प्राप्त की। संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन आचार्य जीवक से बोले, पुत्र, अब तुम मगध जाकर वहां के लोगों की सेवा करो। यह सुनकर जीवक परेशान हो गया। आचार्य उसे दुखी देखकर बोले, कौन सी बात तुम्हें टीस रही है? जीवक बोला, आचार्य, आप तो जानते ही हैं कि मेरा कोई कुल और गोत्र नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगा, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। क्या आप मुझे अपने पास ही नहीं रख सकते? उसकी बात सुनकर आचार्य बोले, वत्स। तुम्हारी प्रतिभा और ज्ञान ही तुम्हारा कुल-गोत्र है। इन्हीं से तुम्हें सम्मान मिलेगा। आचार्य की बातों ने जीवक को नई दिशा दिखाई और वह मगध आ गया। वहां उसने लगन और मेहनत से काम किया। कुछ ही समय में वह पूरे मगध में आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

विचार मंथन

सरकार की आलोचना एवं अभिव्यक्ति अब कानूनन अपराध?

(लेखक- सनत जैन)

भारत की स्वायत्तता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कानून अब सरकार की आलोचना करने पर भी लागू होने लग गया है। इस बात को लेकर देशभर में बड़ी बहस छिड़ गई है। लोग कहने लगे हैं कि सरकार की आलोचना कब से अपराध हो गया है? हाल ही में फेसबुक पर अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान मोहम्मद की गिरफ्तारी, जिस पोस्ट के आधार पर हुई है उसके बाद से यह सवाल आम जनता के मन में बड़ी तेजी के साथ घूम रहा है। हद तो तब हो गई जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया और सुप्रीम कोर्ट ने शर्तो के साथ प्रोफेसर अली खान की अंतरिम जमानत को मंजूर किया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी तीव्र आलोचना भारत में हो रही है। भारत में क्या कानून अब जाति या धर्म के आधार पर लागू होंगे? भारतीय संविधान में अभी तक सभी नागरिकों को समान अधिकार थे, लेकिन जिस तरह से दो घटनाएं सामने आई हैं और पुलिस द्वारा दोनों घटनाओं में जिस तरह की कार्रवाई की गई, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों घटनाओं के बारे में जिस तरह का निर्णय दिया है। उसके बाद देश में यह खुलेआम कहा जा रहा है सरकार और न्यायपालिका किसी पर रहम करते हुए दिखती है तथा किसी निर्दोष को सजा देते हुए दिखती है। यह कैसा तंत्र है? संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानून और नियमों का पालन अब जाति, धर्म और पद देखकर होगा। न्याय भी दक्षिणपंथी, वामपंथी एवं विचारधारा को देखकर किया जाएगा? प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसमें उन्होंने कर्नल कुरैशी का नाम नहीं लिया। सेना और सरकार की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बात कही गई थी उसी पर एक लाइन उन्होंने लिखी थी। दक्षिणपंथी टिप्पणी कर जिस तरह से कर्नल कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं यदि वह माब लिंचिंग और बुलडोजर और नफरत फैलाने वाले लोगों पर भी इसी तरह से प्रतिक्रिया देते तो यह एक अच्छा संदेश होता। इतना लिखना उनके लिए गुनाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर जो बयान दिया गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में जिस तरह की कार्यवाही की है, उसको देखने के बाद अब यह कहा जाने लगा है यदि आप वामपंथी हैं, आप सरकार की नीतियों को लेकर यदि कोई आलोचना करते हैं, आप किसी एक धर्म विशेष से आते हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका भी अपने निर्णय उपरोक्त आधार पर करेगी या सभी को सामान्य रूप से न्याय मिलेगा? सभी नागरिकों को संविधान की सुरक्षा और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने का काम न्यायपालिका करेगी। इसको लेकर अब आम आदमी के मन में संशय उत्पन्न हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अली खान मेहमूदाबाद के ऊपर फेसबुक की वह टिप्पणी जिसमें कोई अपराध ही नहीं बनता है उसके लिए एसआईटी का गठन, उनको आगे कोई अभिव्यक्ति व्यक्त करने पर रोक लगाने, पासपोर्ट न्यायालय में जमा करने तथा विश्वविद्यालय के छात्रों को भी जिस तरह से अभिव्यक्त करने के लिए रोका गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की चर्चा जन-जन में हो रही है। मंत्री विजय शाह के मामले में एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। उन्हें गिरफ्तारी से छूट दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कोई शर्तें भी नहीं लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही निर्णय से न्याय पालिका की निष्पक्षता और न्यायप्रियता भी सवालों के घेरे में आ गई है। देश में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत का राजनीतिक तंत्र युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की तरह संचालित हो रहा है? युगांडा में बोलने की आजादी थी, लेकिन बोलने के बाद आजादी की कोई गारंटी नहीं थी अर्थात चुपचाप देखो बोलने से बचो, सरकार जो कहती है वह करो।

भारत की न्यायपालिका और भारत का प्रशासकीय तंत्र भीड़ तंत्र के दबाव में उसी तरह से चलता हुआ दिख रहा है। भारत में इस तरह के हालात बन गए हैं कौन कानून के दायरे में आएगा और कौन नहीं आएगा, इसका फैसला सरकार ही करेगी। सत्ता पक्ष के लिए अलग कानून होंगे, विपक्षियों के लिए अलग कानून होंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं और जिस तरह की टिप्पणियां विगत वर्षों में सामने आई हैं उसके बाद यह धारणा अब पुष्ट होने लगी है। पिछले कुछ वर्षों में नए भारत के नए नियम कानून से बार-बार लोगों को आपातकाल की याद आ रही है। आपातकाल को कानूनी ढंग से 1975 में लागू किया गया था। वर्तमान में भारत में आपातकाल लागू नहीं किया गया है लेकिन जिस तरह की शासन व्यवस्था है उसको देखकर अब लोगों को आपातकाल की याद आ रही है।

भारत-फ्रांस के बीच दोस्ती और रणनीतिक विश्वास का भी प्रतीक है राफेल

यह बात फ्रांसीसी सीनेट प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में भारत ने कही

नई दिल्ली।

राफेल लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती और रणनीतिक विश्वास का भी प्रतीक बन चुके हैं। यह बात भारत ने आधिकारिक दौरे पर आए फ्रांसीसी सीनेट प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कही। विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में फ्रांस की सीनेट की उपाध्यक्ष कैथरीन ड्यूमा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के समर्थन की बात दोहराई। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की।

प्रतिनिधिमंडल में भारत में फ्रांस के राजदूत भी शामिल थे। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की व्यापक लड़ाई में फ्रांस के दृढ़ समर्थन को दोहराया। बैठक के बाद शशि थरूर ने बताया कि यह यात्रा पहले से तय थी, लेकिन 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बावजूद प्रतिनिधिमंडल ने भारत आने का फैसला किया ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता व्यक्त की जा सके। थरूर ने कहा कि फ्रांसीसी प्रतिनिधियों ने पहलगाम की त्रासदी और उसके बाद की घटनाओं पर भारत के साथ स्पष्ट और मजबूती से समर्थन जताया।

बैठक में भारत की ओर से यह कहा गया है कि फ्रांस से प्राप्त राफेल लड़ाकू विमान केवल रक्षा सौदा नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता और रणनीतिक विश्वास का प्रतीक हैं। इस भावना को वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी दोहराया। रविशंकर 'ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच' के तहत फ्रांस और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों के दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक मंचों पर उजागर करना है। थरूर ने

बैठक में फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल से रविशंकर का परिचय कराते हुए उनके आगामी राजनयिक दौरे की जानकारी दी। इस मौके पर रविशंकर ने कहा कि राफेल साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है॥ रहा है।

संक्षिप्त समाचार

उदित राज ने पीएम मोदी पर कसा तंज- आपकी रगों में सिर्फ पानी, खून और सिंदूर की बात न करें...

नई दिल्ली।

राजस्थान के बीकानेर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भावनात्मक और आक्रामक बयान पर कांग्रेस नेता डॉ. उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने भाषण में कहा था कि अब उनकी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। इसी टिप्पणी को लेकर उदित राज ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी भाषा राजनीतिक नहीं, फिल्मी स्क्रिप्ट राइटिंग लगती है। कांग्रेस नेता उदित राज ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, कि फिल्म निदेशक, उपन्यासकार, कवि और स्क्रिप्ट राइटर की अक्ल क्या घास चरने गई थी? उनको ये आइडिया क्यों नहीं आया? मोदी जी ने कहा कि अब मेरी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस अकेले डायलॉग से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती। इसके साथ ही कांग्रेस नेता उदित राज ने एक और पोस्ट करते हुए पीएम मोदी की सरकार को घेरते हुए कहा, कि मोदी जी, आपकी रगों में सिर्फ पानी है, खून और सिंदूर की बात मत करो तो अच्छा होगा। बहनों के सिंदूर बच न सके आपकी सरकार के निकम्मेपन के कारण। इस प्रकार जहां भाजपा समर्थक पीएम मोदी के इस बयान को एक साहसी और प्रेरणादायक नेतृत्व के तौर पर देख रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावी माहौल बनाने की कोशिश बता रहा है।

अयोध्या का लाल राष्ट्र के लिए कुर्बान, राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को होगा अंतिम संस्कार

अयोध्या।

देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल बनकर 22 वर्षीय लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने सिक्किम में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऑपरेशनल गश्त के दौरान जब उनका एक साथी तेज बहाव वाली नदी में बहने लगा, तो शशांक बिना वक्त गंवाए उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। साथी जवान की जान तो बच गई, लेकिन शशांक खुद नदी की लहरों से नहीं बच सके और शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट शशांक अविवाहित थे और अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के मझवां गद्दोपुर गांव के रहने वाले थे। जानकारी अनुसार 2019 में एनडीए में चयन हुआ था और 2024 में कमीशन मिला। पहली पोस्टिंग सिक्किम में हुई। साथी जवान को बचाते हुए शहीद होने की खबर पाकर शशांक के पिता अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो गए। वहीं मां को शहीदी की खबर नहीं दी गई है। दरअसल शशांक की मां नीता तिवारी हार्ट पेशेंट हैं, इसलिए उन्हें अब तक इस दुःखद खबर से अनजान रखा गया है। यहां बताते चलें कि शशांक के पिता जंग बहादुर तिवारी, मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं और फिलहाल अमेरिका में तैनात हैं। शशांक की बड़ी बहन, जो दुबई में रहती हैं, वर्तमान में अयोध्या पहुंच चुकी हैं। परिवार के कुछ करीबी रिश्तेदार भी मौजूद हैं। शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जा रहा है। शनिवार को जमथरा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना और प्रशासन की ओर से पूरा सम्मान और सम्मानजनक विदाई की व्यवस्था की जा रही है।

मारपीट के पुराने मामले में जेल भेजे गए भाजपा विधायक

दरभंगा।

जिले के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को करीब छह साल पुराने मारपीट के मामले में अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह पूरा मामला 2019 का है, जब दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में मिश्रीलाल यादव और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा था। तीन महीने पहले यानी फरवरी में अदालत ने मिश्रीलाल यादव को दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया था। इसी मामले में वह गुरुवार को अदालत में सजा माफ याचिका दायर करने पहुंचे। विधायक मिश्रीलाल यादव की याचिका पर दरभंगा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। याचिका को निरस्त किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में 23 मई की सुनवाई होनी है, जब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। यह पूरा मामला 29 जनवरी 2019 का है, जो रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में हुआ था। उस समय उमेश मिश्र ने मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव पर पैसा छीनने, अपमानित करने और पिटाई करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ऑपरेशन सिंदूर में शामिल अधिकारी की नौकरी खत्म नहीं होगी

नई दिल्ली।

सर्वोच्च न्यायालय ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका निभाने वाली वायुसेना की एक महिला अधिकारी को सेवा समाप्त करने पर रोक लगा दी है। विंग कमांडर निकेता पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नौकरी के खत्म होने पर तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक विशेष चयन बोर्ड उनके स्थायी कमीशन को लेकर विचार नहीं कर सकता। गुरुवार को जारी किए अपने आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में शामिल हुए लोगों को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर अभी भी अनिश्चितता है कि उन्हें 10 साल की सेवा के बाद सेना में रखा जाएगा या नहीं.. यह गलत है.. सही नीति लाकर इसे ठीक करना चाहिए। न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा, अनिश्चितता की भावना सशस्त्र बलों के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। चूंकि महिला एसएससी अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का कोई सुनिश्चित मौका नहीं है, इसलिए यह 10 साल पूरे होने के बाद यह अधिकारियों के बीच में आपसी कंपटीशन को जन्म देता है। बता दें वायुसेना अधिकारी निकेता पांडे ने 2011 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए वायुसेना में शामिल हुई थीं। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सेवा को 19 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पांडे ने नौकरी खत्म होने के पहले कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनकी रिहाई पर तब तक के लिए रोक लगा दी जाए जब तक बोर्ड उनके स्थाई कमीशन पर विचार न कर ले। पांडे भारतीय वायुसेना की पहली एसएससी अधिकारी हैं जिन्हें अपनी रिहाई पर रोक मिली है। इससे पहले अदालत ने 9 मई को 50 से अधिक महिला सैन्य अधिकारियों की रिहाई पर भी रोक लगा दी थी। इस आदेश को पारित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यह अधिकारी राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसी कोई नीति पेश क्यों नहीं की गई की एसएससी द्वारा चयनित अधिकारी अगर सभी मानदंडों पर खरे उतरें तो उन्हें स्थाई कमीशन किया जा सके।

भारत ने अंडमान सागर के ऊपर एअर स्पेस किया बंद, नोटम जारी

मिसाइल या हथियार प्रणाली की हो सकती है टेस्टिंग

नई दिल्ली।

भारत ने अंडमान सागर के ऊपर एअर स्पेस बंद करने का एलान किया है और एक नोटम जारी किया है। ये केवल कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है। यह नोटम शुक्रवार 23 मई से 24 मई की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह क्षेत्र करीब 500 किलोमीटर लंबा है और सभी ऊंचाई स्तरों पर यात्री विमानों के लिए बैन कर दिया है। यहां मिसाइल या हथियार प्रणाली का टेस्ट हो सकता है। भारतीय प्राधिकारियों ने जारी नोटिस टू एयरमेन (नोटम) के मुताबिक किसी भी यात्री विमान को किसी भी ऊंचाई पर एअर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

नोटम का मतलब एयरमेन को नोटिस है। यह नोटिस पायलटों को जारी किया जाता है, जिनमें उन्हें संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह का नुकसान ना हो। नोटम दूससंचार के जरिए विमानन प्राधिकरणों के पास दाखिल किए जाते हैं। बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नोटम जारी हुआ हो, इससे पहले भी कई बार नोटम जारी किया जा चुका है। सैन्य अभ्यासों और हथियारों के टेस्ट लिए जारी किए गए पिछले नोटम की समीक्षा से पता चलता है कि कई नोटिसों में अस्पष्टता थी, लेकिन इस नोटम के स्थान और कुछ डिटेल

को मिसाइल या हथियार प्रणाली टेस्ट के संकेत के रूप में समझा जा सकता है। पिछले साल अप्रैल में भारत ने अंडमान में हवा से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और मार्च 2022 में एक लॉन्च पैड से विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था।

पाकिस्तान और उसकी सेना आतंकवाद में पूरी तरह से लिप्तः जयशंकर

नई दिल्ली।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान को खुलकर घेरा है। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान और उसकी सेना आतंकवाद में पूरी तरह से लिप्त है। यह सोचना भ्रम होगा कि उन्हें अपने देश में चल रहे आतंकी नेटवर्क की जानकारी नहीं है। जयशंकर ने कहा, हम यह दिखावा न करें कि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान के बड़े शहरों में घूमते हैं। उनके पते और संपर्क सब कुछ ज्ञात हैं। सरकार और सेना दोनों इसमें लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि यदि वहां शहर के बीचोंबीच हजारों लोगों के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हों तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं होगी?

बता दें कि जयशंकर इस समय नीदरलैंड की सरकारी यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य भारत-डच संबंधों को और मजबूत करना है। यूरोपीय संघ में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के नाते यह यात्रा विशेष महत्व रखती है। जयशंकर ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर भविष्य में आतंकवादी हमले होते हैं तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान को यह बात भलीभांति समझ लेनी चाहिए कि अगर फिर कोई हमला हुआ तो उसका जवाब मिलेगा। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। भारत के लिए आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय अपराध है, जिसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और जो भाग अवैध कब्जे में हैं, वे भारत को लौटाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है। इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती।

भारतीय सेना का साहसी कदम है ऑपरेशन सिंदूर

विदेश मंत्री ने 7 मई को किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर'को आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति करार दिया। उन्होंने कहा कि देश को इस कार्रवाई के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यह केवल जवाबी हमला नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक है। आपको इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। यह जवाब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।

भाजपा सांसद निशिकांत का बड़ा आरोपः कांग्रेस ने 1994 में पाकिस्तान से किया था गुप्त समझौता

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई की जानकारी दिए जाने को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान से ऐसी जानकारी साझा करने की परंपरा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, कि 1991 में जब कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार को समर्थन दिया था, तभी भारत-पाक के बीच एक गुप्त समझौते की नींव रखी गई थी। बाद में 1994 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान यह समझौता लागू किया गया। इस समझौते के तहत भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना की तैनाती और रणनीति की जानकारी पाकिस्तान से साझा की जाती थी। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर देश से गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए कहा, कि अगर आज की सरकार द्वारा दी गई जानकारी देशद्रोह मानी जा रही है, तो उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया यह समझौता भी क्या देशद्रोह नहीं था? कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और उन सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिन्होंने यह राष्ट्रविरोधी समझौता किया था।

भाजपा सांसद के इस बयान पर कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जब जानकारी साझा करने का समझौता हुआ तब शांति स्थापित करने की बात चल रही थी, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जब युद्ध के हालात बने थे तब इस तरह की जानकारी साझा करने का क्या औचित्य है।

यह गंभीर मामला है और इस तरह से पूर्व के सरकारों पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 19 मई को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सैन्य कार्रवाई की सूचना दिए जाने पर सवाल उठाए थे।

उन्होंने लिखा था, सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है, उन्हें किसने यह अधिकार दिया? इस प्रकार के बयानों के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी का दौर और तेज रफतार पकड़ सकता है।

किश्तवाड़ मुठभेड़ः ऑपरेशन तृष्णा में दो आतंकी ढेर, एक जवान शहीद

सेना और सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान

जम्मू।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में गुरुवार सुबह से चल रही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच की मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। यह मुठभेड़ किश्तवाड़ के सिंधपोरा छत्रु इलाके में सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई और इसे ऑपरेशन 'तृष्णा' नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेज, 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 7वीं असम राइफल्स और किश्तवाड़ एसओजी की संयुक्त टीम शामिल थी। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। जैसे ही आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, मुठभेड़ शुरू हो गई। वाइट नाइट कोर के अनुसार, मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब भी दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिनमें एक की पहचान सैफुल्ला के रूप में की गई है।

इसके चलते पूरे इलाके को सील कर सघन तलाशी अभियान जारी है। किश्तवाड़ में चल रहा ऑपरेशन 'तृष्णा' अब भी जारी है। सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र को खंगाल रहे हैं और संभावित छिपे हुए आतंकियों को तलाशने में जुटे हैं। सेना की रणनीति साफ है– कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को जड़ से समाप्त करना। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना का एक बहादुर जवान शहीद हो गया। सेना ने उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया है और देशभर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है।

हाल ही में बढ़ी आतंकी गतिविधियां इस ऑपरेशन से पहले पिछले सप्ताह पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों जिसमें आसिफ अहमद शेख, अमीर नजीर वानी और यावर अहमद भट शामिल थे को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके अलावा, शोपियां के जीनपथेर केलर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों का खात्मा भी सुरक्षाबलों ने हाल ही में किया था।

अच्छी नौकरी सुकुन देती है ऐसा नहीं, अपना काम करने वाले ज्यादा खुश

वैज्ञानिकों ने सबसे सुकुन और थकाऊ भरी नौकरियों पर किया अध्ययन

नई दिल्ली।

नौकरी आपको सुकून देती है या तनाव? अब इस सवाल का जवाब विज्ञान ने ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया कि दुनिया की सबसे संतोषजनक और थकाऊ भरी नौकरियों का खुलासा किया है। इस रिसर्च में करीब 59000 लोगों और 263 अलग-अलग पेशों का विश्लेषण किया गया। लोगों से उनकी नौकरी, वेतन, पर्सनालिटी और जीवन के अलग-अलग पहलुओं को लेकर सवाल किए गए। इसके बाद तय किया गया कि कौन-सी नौकरियां लोगों को सबसे ज्यादा सुकून देती है।अध्ययन से पता चला है कि कि सबसे आरामदायक नौकरियों में धार्मिक कार्य करने वाले (जैसे पंडित, पादरी आदि), डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशन, लेखक या लेखक जैसे रचनात्मक कार्य, साइकोलॉजिस्ट, बच्चों के शिक्षक और जहाज इंजीनियर और मेटलवर्कर शामिल हैं। अध्ययन में यह भी खुलासा हुआ कि किन नौकरियों में सबसे कम सुकून है। इनमें सिक्योरिटी गार्ड, वेटर और सर्वे इंटरव्यूअर, सेल्स वर्कर और मेल कैरियर, कारपेंटर और केमिकल इंजीनियर, किचन स्टाफ, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग वर्कर शामिल है। खास बात यह रही कि अच्छी सैलरी या प्रतिष्ठा वाले पेशों का हमेशा उच्च संतोष से संबंध नहीं था। अध्ययन करने वाली रिसर्चर ने बताया कि उसने सोचा था कि प्रतिष्ठा वाली नौकरियां ज्यादा सुकून देगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जिन कामों में उपलब्धि की भावना ज़्यादा होती है, वहां संतोष भी ज्यादा होता है, अगर वह नौकरी बहुत प्रतिष्ठित न हो। उन्होंने यह भी कहा कि खुद का काम करने वाले यानी सेल्फ-एंप्लॉयड लोग ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि

उनके पास अपने समय और काम को नियंत्रित करने की आज़ादी होती है। यह अध्ययन एस्टोनिया के लोगों पर किया गया था, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके नतीजे पूरी दुनिया पर कुछ हद तक लागू हो सकते हैं।

हाफिज की जुबान बोल रहा पाक सेना का अफसर कहा- हमारा पानी रोका तो हम सांसे रोक देंगे

नई दिल्ली।

ये जगजाहिर है कि पाकिस्तान की सेना भी आतंकियों के साथ खड़ी हुई है। उसकी जुबान भी आतंकी जैसी ही हो गई है। ठीक वही जुबान जिस तरह से आतंकी हाफीज सईद बोलता है। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे, तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। बता दें कि उनका यह बयान उस वीडियो से मेल खाता है जिसमें मुंबई आतंकी हमलों (2008) के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ठीक यही शब्द कहते सुना गया था। यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्म एक्स पर वायरल हो रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि के कुछ हिस्सों को निलंबित कर दिया था। भारत ने यह कदम पहलगाम में हुए आतंकी हमले के एक दिन उठाया था। इसके बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। भारत ने बार-बार कहा है कि खून

और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। यह सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन पर सख्त रुख का संकेत देता है। बता दें कि 1960 में विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई यह संधि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे को दोनों देशों के बीच नियंत्रित करती है। इसके तहत दोनों पक्षों को जल उपयोग के बारे में नियमित जानकारी साझा करने की भी आवश्यकता होती है।

पहला कॉलम

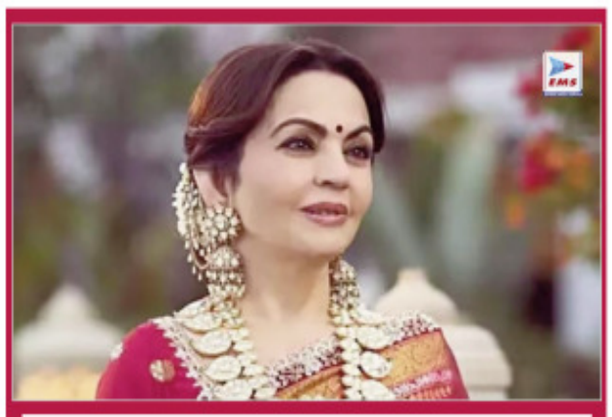

नीता अंबानी न्यूयॉर्क में कर रही 'इंडिया वीकेंड' इवेंट

दुनिया को कराएंगी भारतीय सभ्यता से रुबरु

नई दिल्ली।

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी चर्चा में बनी रहती हैं। 2023 में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंट्रल के उद्घाटन को लेकर वह काफी सुर्खियों में रही थीं। इस बाद नीता ने भारत की कला, संस्कृति-परंपराओं और विरासत को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क में 'इंडिया वीकेंड' के आयोजन का एलान किया है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम 12 से 14 सितंबर, 2025 तक अमेरिका के मशहूर लिंकन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में डांस, म्यूजिक और फैशन का जलवा नजर आएगा। इस बारे में नीता ने कहा कि संस्कृति लोगों को एक साथ बांधती है। ऐसे में हम यह देखना चाहते हैं कि हम भारतीय कलाओं और कलाकारों को दुनिया की रचनात्मक कल्पना के सामने और केंद्र में कैसे रख सकते हैं और इसके लिए लिंकन सेंटर से बेहतर कोई जगह नहीं है। इस वीकेंड कार्यक्रम में म्यूजिक, थिएटर, फैशन शो, भारतीय व्यंजनों और पारंपरिक शिल्प की विशेष झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान मशहूर शेफ विकास खन्ना के खास व्यंजनों का स्वाद भी लोगों को चखने का मौका मिलेगा। इस बारे में विकास ने कहा कि एनएमएसीसी लोगों को भारत को समझाने का अद्भुत काम कर रही है। इसके मंच और भारत को दुनिया के सामने लाने के विजन के साथ, इसका हिस्सा बनना वाकई सम्मान की बात है। फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए मेन्यू तय करने का काम चल रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक ग्रैंड वेलकम से होगी, जिसमें सिर्फ आमंत्रित किए गए मेहमानों की एंट्री होगी। इसमें अंबानी के हैंडलूम एम्पोरियम स्वदेश के लिए फैशन शो भी होगा। साथ ही इस शो के लिए मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ड्रेस डिजाइन करेंगे, जिन्होंने हाल ही मेट गाला में रेड कार्पेट पर अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल और ऋषभ शर्मा भी अपनी परफॉर्म देंगे। इस कार्यक्रम में द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल सिविलाइजेशन टू नेशन की पांच प्रस्तुतियां भी दिखाई जाएंगी, जिसका निर्देशक फिरोज अब्बास खान ने किया है। इस म्यूजिकल ड्रामा में 100 से ज्यादा कलाकार, मैक्सिममलिस्ट सेट और मल्होत्रा के तैयार आउटफिट्स के साथ करीब 7,000 साल के भारतीय इतिहास को बयां करेंगे।

आज पुंछ पहुंच रहे राहुल गांधी, पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हाल ही में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मिलने के लिए शनिवार को पुंछ जाएंगे। इसकी जानकारी एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश ने दी। इस तरह से राहुल गांधी का ये जम्मू-कश्मीर का दूसरा दौरा होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट में कहा, राहुल गांधी 24 मई को पुंछ का दौरा करने वाले है। इस दौरे में राहुल हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान पीड़ित परिवारों से मिलने वाले है। उन्होंने कहा, इसके पहले वे पहलगाम आतंकवादी हमले में घायल हुए लोगों और कई अन्य पक्षों से मिलने के लिए 25 अप्रैल को श्रीनगर आए थे। उन्होंने उस समय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की थी। हमले के बाद बीते महीने अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि आतंकवादी हमले के पीछे का विचार देश के लोगों को बांटना था और यह जरूरी है कि भारत आतंकवाद को हमेशा के लिए हराने के लिए एकजुट हो जाए। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने के बाद करीब दो सप्ताह पहले पुंछ सेक्टर में गोलाबारी बढ़ गई थी।

इसरो ने 2025 को गगनयान वर्ष किया घोषित, अब तक कर चुका है 7200 टेस्ट

इस साल के अंत तक पहला मानव रहित मिशन व्योममित्र लॉन्च किया जाएगा

कोलकाता।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख वी नारायणन ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित करते हुए इसे इसरो के लिए बहुत ही खास साल बताया है। उन्होंने कहा कि अब तक 7200 टेस्ट किए जा चुके हैं और करीब 3000 टेस्ट करना अभी बाकी है। इस समय गगनयान कार्यक्रम की तैयारियां दिन-रात चल रही है। गगनयान कार्यक्रम को दिसंबर 2018 में मंजूरी मिली थी। इसका उद्देश्य भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत इंसानों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जरुरी तकनीकों को विकसित किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यह साल हमारे लिए बहुत अहम है। हमने इसे 'गगनयान वर्ष' घोषित किया है। इंसानों को भेजने से पहले तीन मानव रहित मिशनों की योजना बनाई गई है, जिनमें से पहला मिशन इस साल दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसरो ने अब तक 7200 से ज्यादा टेस्ट किए हैं और करीब 3000 परीक्षण अभी और करना बाकी है और काम 24 घंटे चल रहा है। इसरो प्रमुख नारायणन ने हाल ही में पूरे हुए स्पाडेक्स मिशन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी प्रदर्शन मिशन के लिए केवल 10 किलो ईंधन तय किया गया था, लेकिन यह मिशन महज पांच किलो ईंधन में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, जिससे शेष ईंधन का इस्तेमाल आगामी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। स्पाडेक्स मिशन, इसरो की वेबसाइट के मुताबिक एक किफायती तकनीकी प्रदर्शन मिशन है जिसमें दो छोटे सैटेलाइट को पीएसएलवी से प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया गया।

वी नारायणन ने आगे कहा कि 2025 में कई अहम मिशनों की योजना बनाई गई है। इसमें नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट भी शामिल है, जिसे भारत के स्वदेशी लॉन्च वाहन से लॉन्च किया जाएगा। एक कॉमर्शियल मिशन और संचार सैटेलाइट भी इस साल कार्यक्रम में शामिल है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक व्योममित्र नामक मानव जैसे रोबोट के साथ पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद दो और मानव रहित मिशन होंगे। उन्होंने कहा है कि इस साल करीब हर महीने एक लॉन्चिंग की जाएगी।

साल के आखिर तक पहला मानव रहित मिशन व्योममित्र के साथ लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद दो और मानव रहित मिशन होंगे और 2027 की पहली तिमाही तक हम पहले मानव को अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसरो की ये तैयारियां भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही हैं।

गगनयान मिशन के सफल क्रियान्वयन के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष में इंसान को भेजेगा। इसरो प्रमुख ने गुरुवार को कहा कि संगठन खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहा है और यह भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष विभाग देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। नारायणन ने कहा कि फिलहाल कक्षा में हमारे 57 सैटेलाइट हैं, जो मौसम के पूर्वानुमान से लेकर सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाने तक, विभिन्न मुद्दों पर ताजा जानकारी और डेटा प्रदान करके जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पीएसएलवी-सी61 मिशन की हालिया विफलता को इसरो की कामयाबी में एक अपवाद बताया है। उन्होंने कहा कि यह झटका किसी भी तरह से इसरो के भविष्य के कार्यक्रमों जैसे गगनयान को प्रभावित नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन

भारत मंडपम में दो दिन चलेगा कार्यक्रम, निवेश को मिलेगा नया आयाम

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय समिट पूर्वोत्तर भारत में निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक व घरेलू निवेशकों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। समिट के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ-ईस्ट को भारत की विविधता की आत्मा बताते हुए अपने संबोधन में कहा, कि भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट इसका सबसे डाइवर्स हिस्सा है। पूर्वोत्तर के हर राज्य में अद्भुत सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आर्थिक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट को इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी की त्रिमूर्ति से जोड़ने का काम किया है। भारत मंडपम में आयोजित इस दो दिवसीय समिट में बी2बी और बी2जी बैठकें आयोजित की जाएंगी। इससे उद्योग जगत और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच साझेदारी के अवसर तलाशे जाएंगे। इसमें मिनिस्टर लेवल सेशन्स भी आयोजित होंगे ताकि नीति निर्माताओं और निवेशकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद हो सके।

मुख्य फोकस सेक्टर्स

इस समिट में प्रमुख रुप से पर्यटन, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही हस्तशिल्प और बांस उद्योग पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की इस सेक्टर्स में निवेश के आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पूर्वोत्तर राज्यों को मिले। 2023-24 में जीएसडीपी- 9.26 लाख करोड़ रुपये। 2014-15 से 2021-22 के बीच विकास दर- 10.8 प्रतिशत (राष्ट्रीय औसत 8.1प्रतिशत से अधिक) रही।

पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार के अनुसार, समिट से पूर्वोत्तर में औद्योगिक आधार को मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

ऑपरेशन सिंदूर से साफ हो गया कि पाकिस्तानी सेना खुद आतंकियों के साथ मिली हुई- शाह

अब भारत बदल गया है अब जवाब देना सीख गया

नई दिल्ली।

मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर तीखा हमला कर कहा कि वह आतंकियों को पनाह और समर्थन देता है। उन्होंने यह बात बीएसएफ अलंकरण समारोह के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। गृह मंत्री शाह ने कहा, जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान में मौजूद आतंकी शिविरों को तबाह करती हैं, तब पाकिस्तानी सेना नागरिक इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमला करती है। पाकिस्तान की इन हरकतों से साफ हो जाता है कि पाकिस्तानी सेना खुद आतंकियों के साथ मिली हुई है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 22 मिनट में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के नौ आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शाह ने दो टूक कहा कि भारतीय सेना ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तानी सेना या उनके सैन्य अड्डों को। गृह मंत्री शाह ने कहा, हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब आतंक का जवाब आतंक से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से उजागर हो गया कि पाकिस्तान में आतंकवाद केवल मौजूद नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित है। शाह ने 2016 की सर्जिकल और 2019 के एयर स्ट्राइक का जिक्र कर कहा कि भारत पहले चुप रहता था, लेकिन अब जवाब देना सीख गया है। इस मौके पर बीएसएफ की तारीफ कर केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ का योगदान अमूल्य है। उन्होंने बताया कि तकनीकी चुनौतियों वाली सीमाओं पर उन्नत निगरानी तकनीक अपनाई जा रही है। जम्मू-कश्मीर की हालिया यात्रा का जिक्र कर उन्होंने कहा कि सीमाओं पर अब तकनीक आधारित सुरक्षा समाधान लागू किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने अंत में 1971 के युद्ध का उल्लेख कर कहा कि बीएसएफ के जवानों की वीरता को भारत और बांग्लादेश दोनों कभी नहीं भूल सकते।

एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम जल्द डिलीवरी के लिए रुस जाएंगे डोभाल

-पाक पीएम और मुनीर की बढ़ी टेंशन, एस-400 ने ही पाक में मचाई थी तबाही

नई दिल्ली।

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की टेंशन अब और बढ़ने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान की तबाही का और सामान लाने भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। अजीत डोभाल की इस यात्रा का मकसद बाकी बचे हुए एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर जोर देना है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मॉस्को यात्रा के दौरान अजीत डोभाल सुरक्षा मुद्दों पर उच्च प्रतिनिधियों की 13वीं इंटरनेशनल मीटिंग में भाग ले सकते हैं। यह बैठक 27 से 29 मई तक मॉस्को में होना है, जिसकी अध्यक्षता रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव करेंगे। इस दौरान अजीत डोभाल बाकी दो एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी का मामला भी बैठक में उठा सकते हैं। एस-400 भारत के लिए कितना अहम है, यह ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान तो उसके नाम से ही खौफ खाने लगा है। भारत के पास अभी 3 एस-400 है। भारत में इसका नाम सुदर्शन चक्र है। बाकी बचे एस-400 आने से पाकिस्तान की और टेंशन बढ़

जाएगी। दरअसल, भारत ने 2018 में 5.4 बिलियन डॉलर में एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट्स खरीदी थीं। इसमें से तीन सिस्टम की डिलीवरी हो चुकी है। दो और सिस्टम का इंतजार है। रूस-यूक्रेन युद्ध और दूसरी चुनौतियों के कारण एस-400 के चौथे स्क्वाड्रन के 2025 के अंत तक और पांचवें स्क्वाड्रन के 2026 में आने की उम्मीद है। बता दें एस-400 की क्षमता हाल ही में तब सुर्खियों में आई, जब इस डिफेंस सिस्टम ने 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी अटैक को तबाह करने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। इसने पाकिस्तान के एक भी हमले को सफल नहीं होने दिया। पाकिस्तान से जितने भी ड्रोन और मिसाइल आए, सबको एस-400 ने हवा में ही मार गिराया।

मुकेश अंबानी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का श्रेय सेना और पीएम मोदी को दिया

नई दिल्ली।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने इसक श्रेय भारतीय सेना के वीर जवानों और देश के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी घटना के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना की इस सफलता पर मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं पीएम मोदी को 'ऑपरेशन सिंदूर' की शानदार सफलता के लिए सलाम करता हूं। यह सफलता उनके दृढ़ संकल्प और हमारी सशस्त्र सेनाओं की अद्वितीय बहादुरी का प्रमाण है। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं और इस सीमित कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था।

हिंसा मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने छह छात्रों को निष्कासित किया

नई दिल्ली।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने 25 अप्रैल को कैंपस में हुई हिंसा के मामले में छह छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया है। साथ ही, 20 अन्य छात्रों को कारण बताओ नोटिस दे दिया है। प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, निष्कासित छात्रों पर तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर प्रतिबंध लगा है।

यह फैसला विश्वविद्यालय परिसर के गेट नंबर 8 के पास दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के समीप हुई हिंसक झड़प के बाद लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो छात्र समूहों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। इसमें छात्रों और कुछ बाहरी लोगों ने लाठियों, पत्थरों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल कर एक-दूसरे पर हमला किया। विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों और अधिकारियों

के हस्तक्षेप पर भी असामाजिक तत्वों ने न केवल गालियां दीं, बल्कि शारीरिक हमले भी किए। प्रशासन ने निष्कासित छात्रों को आईडी कार्ड लौटाने और छात्रावास एक सप्ताह में खाली करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कारण बताओ नोटिस प्राप्त छात्रों से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, अन्यथा उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ऑपरेशन सिंदूरः पाकिस्तान अपनी झूठी जांबाज़ी के सुना रहा किस्से

नई दिल्ली।

पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पाकिस्तान को तबाड़तोड़ हमलों से दहला दिया, वो शहबाज़ शरीफ और आसिम मुनीर अच्छी तरह से जानते हैं। वो बात अलग है कि वो इसे नकारते हुए पाकिस्तान अपनी झूठी जांबाज़ी के किस्से सुना रहा है। अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी इस बार की पुष्टि कर रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों की कब्र खोद दी थी। पाकिस्तान एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में हुए अपने नुकसान पर पर्दे डाल रहा है, वहीं दिन गुजरने के साथ-साथ उसका झूठ खुलता जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकाने को यूं धुआं-धुआं कर डाला कि उसे संभलने में 11 दिन का वक्त लग गया। अब भी बेशर्म पाकिस्तान और उसके फेल्ड मार्शल अगर ये कहें कि उन्होंने जीत हासिल की है, तो इससे बड़ा झूठ और क्या होगा?

नुकसान के बाद भी पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख को इस ऑपरेशन के बाद प्रमोशन दे दी गई। आसिम मुनीर को भले ही फील्ड मार्शल बनाकर पाकिस्तान उसे सम्मान दे रहा है लेकिन उसके फेल्ड ऑपरेशन की तस्वीरों को दुनिया कैसे नकारेगी। बिना किसी सबूत के पाकिस्तानी सेनाओं ने अपनी जीत घोषित कर दी और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ सीज़फायर के डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कहते नहीं थक रहे। आखिरकार पाकिस्तान की जान तो उन्होंने ही बचाई है।

11 दिन में भरे गए गड्ढे

भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को रगोधा और रहीम यार खान हवाई अड्डों पर वायुसेना ने जो सटीक हमले किए, उसे पाकिस्तान झेल नहीं पाया। हमले के 11 दिन बीत जाने के बाद जाकर बड़े-बड़े गड्ढों को भरा जा सका है और दोनों पाकिस्तानी हवाई ठिकाने फंक्शनल हो चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि होती है कि पाकिस्तान के सरगोधा और रहीम यार खान हवाई अड्डों पर रनवे की मरम्मत पूरी हो चुकी है।

6-9 मीटर चौड़े गड्ढे देखे गए थे

ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसके तहत सटीक और सधे हुए हमलों में वायुसेना ने पाकिस्तान के सरगोधा, रहीम यार खान, नूर खान, जैकोबाबाद, भोलारी जैसे प्रमुख हवाई अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया था। मैक्सार टेक्नोलॉजीज और अन्य स्रोतों से प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों में हमलों के तुरंत बाद रनवे पर बड़े गड्ढे दिखाई दिए थे। रहीम यार खान में, जो शेख जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साझा रनवे है, 6-9 मीटर चौड़े गड्ढे देखे गए, जिसके कारण यह रनवे पूरी तरह से अक्षम हो गया था। वहीं सरगोधा, जो पाकिस्तानी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना है और जहां एफ-16 और जेएफ-17 जैसे उन्नत लड़ाकू विमान तैनात हैं, वहां भी रनवे के चौराहे के पास दो बड़े गड्ढे बन गए थे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717